

**सुनालिया
ज्वेलर्स**
हीरा, स्वर्ण, हॉलमार्क ज्वेलरी,
रजत, राशि नग के विक्रेता
मो. 94255-32524, 94241-43922
पावर हाउस रोड, कोरबा

**अब जाग जाओ..., डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर पूर्व आरबीआई
गवर्नर की सरकार को चेतावनी, दिया ये सुझाव**

एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश नाकाम **बिहार की जनता होशियार, कटे तोट** **श्रीनगर में बाढ़ जैसी स्थिति** **बिजली-**

आतंकवाद का भय पैदा हो गया
30 जुलाई को भी सेना ने
आतंकवादों संगठन लश्कर-
ए-तय्यीन को हरा दिया।
सैनामहदी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल
गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने
महानगरों में आतंकवादियों को
महानगरों में आतंकवादियों को
महानगरों में आतंकवादियों को

चनार कांस न ऐस पर पोट
किया, जम्भू-कर्मणोर पुत्रिस से
मिली खुशिया जानकी के आधार

10 करोड़ से अधिक की जीपासी गरी का खलाया

नईदिली, 28 अगस्त (एजेंसी)।

बारिस की वजह से बाग और खलमाव के पुरत

[illegible]

सिक्किम के गारू व काम्पेरोलाजी विल्विक भारी बारिश और लैंडस्लाइड से ज़ाम-हिमानल को तबाह तिथारक पात्र के बंगले में

डॉ. आर.के. अग्रवाल - पारमार्थिक सम्भव - डॉ. राशि अग्रवाल

सुविधाएँ- गंजापन, मससे हटना, दाद खाज खुजली, एक्जिमा, एर्जर्जी, सड़े नाखून, कुष्ठ रोग, काले दाग, मुंहासे, बाल झड़ना, सेक्स की कमी, रीढ़ पतन, धात, इलाको कल वॉशिंग ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। यातायात उप-पै है। मेमोम विभाग का भी फंक्शन है।

मो. 9203907928, 9826389894 (वलीनिक) नहीं ले रही है। पहली इलाकों में लगातार कई दिनों से बाहिरा बंद है। उसके बाद मई में 216 सड़कें बंद हुईं। कुछ दिनों के बाद बाहिरा के भी निवासियों को बाहिरा के बाहर बाघ पुराणियों को सौंप दिया गया। विधायक नेवा सिंह गौर के बेटे अभिराम सिंह गौर से खसाला सिंह गौर तो उन्होंने कहा।

परातः एकादश्यां च न हर्षात् न च भयं ।
 पण्डित-कुलं खलु पण्डितस्य न हर्षात् न च भयं ।
 यो हि, जिसके चेहरे योग, दमारा और अन्य संकीर्णताएँ पूर्ण
 सख्य होती या रही हैं। यहाँ छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता तो
 खराब होता या रही है। यहाँ छोटी गाड़ियों के लिए रास्ता तो

पुष्टिवाचा है। भयम् न जहो लोभस्यस्य स भयं नुकमान च
 खल्वानु न हर्षं चाप्यनुमानं च यदुच्छा। यद् भयं न हर्षं च
 यो और न ही कभी परेशान होता या रहता है। यहाँ से हमको नही, बल्कि
 बालिक-संघों की तरह थीं। यहाँ 5 दसली की वह भी नेहरूजी नहीं, 2.45

खाली गया है, लेकिन हमारा ठीक अंश भी फसल है। लाल कपाड़ें रुपये से अधिक हैं। रह रही थीं। हम उससे शादी के लिए रिश्ता भी ढूँढ रहे थे।

को अलग-अलग जिलों में जिम्मेदारी दी गई है तथा वरिष्ठ पदाधिकारियों रायस्थान रेंजों के कार्यालय में अधिकृत भारतीय सैनिकों को नियुक्त किया गया है।

विद्युत् उपभोक्ताओं को जाबानबाजी, बिजलीपट्टी में महामंडल क्षेत्र के अधिकांश स्थलों पर विद्युत् की एक से. घण्टावार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्युत् महासंघ महासंघ के उपमहानिदेशक द्वारा बोनस, दूध, बी.एस. राजपुत, राजनंदगांव में संयुक्त महामंत्री लिखित कराल दुर्घटना बस्तर में कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठ प्रशासक शाखा में महामंत्री निवृत्त बंधु, राणागढ़ में एस.पी. कटरवाल, अफियापुरा में दीलेश चौधरी आदि शामिल होंगे। सभी जगह जोरदार प्रदर्शन कर जापान सीमा पर जाया। इसके बाद राज्यपुर मुख्यालय में जारी व घेराव को रणनीति बनाई जाएगी।

नाम सुधार सूचना

मैं भरत कुमार आत्मज जगन प्रसाद जाति रजवार आयु 53 वर्ष निवास वार्ड नंबर 20 खरवत तहसील वैकुण्ठपुर जिला कोरिया छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ मेरा आशय क्रमांक कार्ड क्रमांक 9831 9 258 5371 है जिसमें मेरा पुरेला नाम नंद भरत दर्ज है इसको सुधार कर वास्तविक नाम भरत कुमार दर्ज करना चाहता हूँ।

सूचना ग्रहण करें।

અનમોલ વચન.....

हम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं,
अक्सर हमें वही लोग सबसे ज्यादा धोखा देते हैं।

कानूनी समाधान की पहल

केंद्र सरकार अब ऐसे विधेयक ले आई हैं, जिनके कानून बनने के बाद गभीर अपराधिक मामलों में जेल जाने की स्थिति में प्राधान्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रियों को उनके पद से हटाने का प्रावधान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले दो मुख्यमंत्री पद पर रहते गिफतार किए गए थे उनमें से झारखंड के हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा देकर भारत की संवैधानिक व्यवस्था को नैतिक दुविधा से बचा लिया, लेकिन जब बारी आरंभिक केजरीवाल की आई, तो उन्होंने भारत की उजनीति व्यवस्था में आ रही चमत्कहत को उजागर कर देने की रणनीति अपनाई। केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। तब वह अजीबोगरीब स्थिति बनी कि एक मुख्यमंत्री जेल में रहते हुए वहीं से सरकार चलाने का दावा कर रहा था। भारत में आज जो सिपायी चूत हैं, उसके बीच ऐसी विडंबनाओं की गुंजाइश लगातार बनी हुई है। नियम या कानूनों को जब अत्यधिक खींच दिया जाता है, तो मर्यादाओं का तार-तार होना स्वाभाविक परिणाम होता है। अब केंद्र ने ऐसी परिस्थितियों के कानूनी समाधान की पहल की है। वह ऐसे विधेयक ले आया है, जिनके कानून बनने के बाद गंभीर अपराधिक मामलों में जेल जाने की स्थिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रियों को उनके पद से हटाने का प्रावधान हो जाएगा। जेल गए पादशिकारी की रिहाई के बाद उसे पद पर वापस लाने का प्रावधान भी किया जा रहा है। अगर आज वह धारणा होती कि संवैधानिक व्यवस्था सामान्य ढंग से काम कर रही है और कानून लागू करने वाली एजेंसियां नियंत्रण से ठीस तथ्यों के आधार पर कदम उठाती हैं, तो प्रस्तावित एक कानून को एक स्वस्थ पहल माना जाता। लेकिन दुर्भाग्य से आज धारणा असाध्य उलट है। प्रचलित धारणा वह है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियां रणनेताओं के दल और उनकी राजनीतिक प्रतिक्रिया को देख कर उनके अपराध तय करती हैं। ऐसे में प्रस्तावित कानून पर विषेशी खेमी में अशंका पैदा होना लाजमी प्रतिक्रिया माना जाएगा। इस पर केंद्र ने विषेशी से कोई संवाद नहीं किया है। इस कारण अशंकाओं की गुंजाइश और भी ज्यादा है। इसलिए उचित होगा कि एंशकाओं लागू करने के पहले केंद्र उस पर सभी पंशों की भरसे में है। इस बारे में आम सहमति बनाएं जाने की जरूरत है। वरना, प्रस्तावित कानून को सता के केंद्रिकरण के एक और प्रयास के रूप में देखा जाएगा।

राशिफल

[illegible]

भारत के डॉग-लवर्स में मातम

//श्रुति व्यास//

सीधी बात पर आते हैं। इसी वजह से वे अतीव रोमांच में आतम में हैं। दुकानें बंद, बिस्बेड हटा, जैसे सकाकर उनका उद्देश्य कर्म से 'कठनों' को पोसा से उठा लेते हैं। डीबी-एन राय, सहाय पर जायम, मुक्ता व्याघ्राणीय कट अर्जी - वह भी ठीक ठीक बाल, क्योंकि 1.4 अब की आबादी वाले इस मुक्त में, यही है इमरजेंसी। ऊपर असली भारत में - बादाम लुटे, बाल केफे ओर अविष्टर को दुनिया से बाहर - लोग थोड़ी ख्याती भीयन चीनी से अजुन लेंगे हैं। कोई ठुंसे से बच रहा है, कोई कैंप में, कोई अर्जी जर्नल जर्नल के आदमी बाशिर्षा में न गिर जाने की दुआ कर रहा है। इस दिवाली जलूरी सामान पर जीएसटी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन किफ पकड़ पड़ता है। कब तक कुरीत सहे हैं, देश खून बहा ले। पर अगर सबको पता है, अगर सबको पता है कि जल तो को की!

[illegible]

और वह घबराहट क्यों? अचानक रेबीज महामारी का डर क्यों, अगर कुत्तों को उठाना गया तो क्या खाना खिजाना रातोंरात बदल गया? होना तो वह चाहिए कि अगर एक मुकामल व्यवस्था मिले— कामधुन्य शेड्यूल, बेदगा लागू करने वाला सिस्टम। लेकिन नहीं। मोशल मौजिया पर मैंने एक महिला का वीडियो देखा— अचानक टूट पड़ा हो जैसे, वह हंफते-रते कह रही थी: अगर वे मेरे बच्चे ले गए तो मैं पर जाऊँगी। उनके 'बच्चे' गली के खोजते और क्यों वे बच्चे हैं, तो ट्रैफिक में भटकते और कुत्तों में खाना खोजते क्यों छोड़े गए? एक और विलपन में भयंकर को बच्चों की तरह गोद में लेकर नारे लगा रहे: यह मेरा अधिकार है।

है सड़क पर जीने का! माफ़ कीजिए, सड़क पर जीना किसी का अधिकार नहीं है - न कुतूब का, न गायों का, न बंदों का, न ही इसमनो का। लेकिन हमारी अंधजाल बिचारी असली शेल्टर बनाते या नगण्यपालिका की ब्रम्हा सुधारने से ज़्यादा नैतिक नाटक पसंद करती है। और उससे भी बदतर - वे उस छंदे लड़के पर एक आंसू नहीं बहाते जो साहसिक चलावे निकला और हर लौकिक नहीं आया। मर्लिन के कुरों के झुंड ने उसे नचाने का कर मार डाला। उसका छेछा शरीर उन दांतों से फाड़ा गया जिन्हें देखने तक से आप डंका करती हैं।

आप - अमीर, वोकर, भौकाली, तुत - जिनके पास ड्रियिया हैं, अनुभव हैं, दिमाग हैं। जब कोई अराजकता में थोड़ा सा भी अनुशासन लगाने की कोशिश करती है, तो छिछर हो जाता। दान अधिनाश, नीति सुलझ दीजिए। रोने की कहानियाँ और ऑल्लाइव पेटीशन मत चलाए। आपको लगता है न्यूयॉर्क टाइम्स आपके साथ खड़ा है। उनके न्यूज़रूम में वे सिर हिला रहे हैं, या शायद हंस रहे हैं। आप अपने देश को देश को दोष देकर खलंग बना दिया है।

मैंने उसी दिन कहा था जब आदेश आया: समस्या कुत्ते नहीं हैं - हम हैं। और वही अब एक्टिविस्ट, आवारा पशुओं के प्रेमी इसे साबित कर रहे हैं।

[illegible]

तो सवाल वही - देश जा कहाँ रहा है?
कहाँ नहीं - अगर यही हमारी लड़ाई है। और अगर इस देश का पतन-
लिखा तबका सिर्फ आवाज़ कुतों के लिए उठ खड़ा हो सकता है, जबकि
बाकी सबकुछ खुद कुतों के हवाले हो चुका है, तो शायद, सचमुच, हमें
भी उनके साथ ही जाना चाहिए।

अमित शाह के बयान को लेकर पूर्व जजों का आपस में ही भिड़ना गजब राजनीति है

//नीरज कुमार दुबे //

दरआसन, सम्यक्का इन्द्र बा की नई है कि कोरी सती और कोराना। आसनी चिना वत, यह पूछ जनी के समुद्र-आराजनी की धाया में एक-दूसरे से पीछे रहें। इससे न्यायपालिका की विधिसमस्याएं जो पता पड़ती हैं, राजनीति में एक-दूसरे आगे-पिछाये कोना, समूहों का टुकाना और बचावों की तलवारें चलाना कोई बात नहीं है। पन्तु हाल के दिनों में यह परंपरा अब न्यायपालिका के जुड़े संवैधानिक खंडों तक फैल गई है। सत्त्वा प्रभुत्व समूहों और राजनीति आसनी की टोपियों पर प्रतिक्रिया देते हुए पृथक् पृथक् के दो खोमें में खूना चलाना सामने आया है। यह दूसरा अस्मरुण्ड इन्फ्रिग है न्यायिक न्यायपालिका को सदरे राजनीति से अलग और पृथक्स्थ का प्रतीक माना जाता रहा। अब जब जूट दो समूहों में बाँटकर सार्वजनिक बचनबाजी कोने लगते हैं, तो यह संदेश जाता है कि न्यायपालिका की गति और स्वतंत्रता केवल कोराने हैं, लखवारी में नहीं।

यह सही है कि कोई भी व्यक्ति व्यावसायिक रूप से बड़ा अपने विचार रखने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि कोई जैन राजनीति में प्रवेश करता है, तो उसे उसी संस्था के प्रतिभालत पर आरोपना भी करना होगा। लेकिन जैन धर्म की रचना में पूर्व व्याघ्राधीश व्यावसायिक तौर पर व्यापक करने किसी नेता या उम्मीदवार के पक्ष-विषय में अंतरा है, तो वे केवल व्यक्तियों पर अमर नहीं डालते बल्कि पूर्व व्यावसायिक समुदाय की निष्पक्षता पर सहित छाह कर रहे हैं। दरअसल, समस्या इस बात को नहीं है कि कौन सी पार्टी के कौन कौन एकदम असली चिन्ता यह है कि पूर्व राज्यों के समूह अमर राजनीति को भाषा में गुलामी करने से भिन्न रहे। सर्वेक्षण व्यावसायिका की विश्वसनीयता पर निर्भर पहुँचाना है। लोकतंत्र में अद्वितीय का सम्मान इसलिए होता है क्योंकि लोग मानते हैं कि वह राजनीति से परे है।

यदि वह भाषण ही है तो यह न केवल न्यायाधीश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए भी थाकत होगा। अतः समग्र न्याय ही किन्तु न्यायाधीश ही केन्द्रित को संयोजन करने पर उद्देश्य से बचाव। व्यक्तित्व या स्वतंत्र और सर्वव्यापी रूप से गवर्नरिज्म का हिस्सा बनने में अंतर है। न्यायाधीश को गवर्नर बचाने केवल विद्वान् जनों का अहसास ही है कि न्यायिक सर्वव्यापी जहाँ भी कायम है। न्यायाधीशत्व का सम्मान इसी में है कि वह राजनैतिक अखण्ड न बने, वैश्व समान के अतिरिक्त नैतिक कानूनीकरण भी नही। जहाँ तक पर विचार को बना है तो आशंकित बात है कि कानूनीकरण मुझे अलग रूप के केंद्र में है यदि भाषण में कलह का किर्तुष्य सुरक्षा में है तो न्यायिक सुझुम निमित्त से न्यायाधीश को अक्षर ही अखण्ड। अतः न्याय का ज्ञान था कि अगर वह निमित्त नही दिया गया तो न्यायस्वरूप 2020 तक ही का होना है। अतः समग्र पर प्रक्रियायें जहाँ एक संयोजन के समान 18 संवैधानिक न्यायाधीशों ने अमित शत्रु को पर लिखत उनको टर्म्पणी को दृष्टिकोणों बनाया और अतः नैतिक हमला करने से बचने को सहाय है।

उन्के अनुसार यह न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ है। इसके ठीक अगले दिन 56 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का समूह सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चार पूर्व न्यायाधीश और पूर्व मुख्य न्यायाधीश- पी. सदाशिवम, रंजन गोहोई, एके सीकरि और एमआर शाह शामिल थे। इन न्यायाधीशों ने अपने वक्तव्य में कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता राजनीतिक बयानबाजी की छाल नहीं बन सकती।

बयान में कहा गया कि बार-बार कुछ पूर्व न्यायाधीश राजनीति से घेरित होकर बयान जारी करते हैं और न्यायपालिका को पक्षपाती दिखते हैं। बयान में कहा गया कि यदि कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजनीति में आता है (जैसे जस्टिस रेड्डी ने विपक्ष का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनकर किया), तो उसे उम्मीदराजनीतिक क्षेत्र में जवाब देना होगा, न कि न्यायपालिका की दाल के पीछे छिपकर।

देखा जाये, यह प्रकरण इस बात को उमंगर करता है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता और न्यायधीनता की व्याख्यात गुणवत्तावत् संरक्षण के बीच की कानूनी सहानुभूति हो रही है। अमिश शर्मा के आलोचक पूर्व मानते हैं कि न्यायधीनता का ध्वनि संकेत को गरिमा में पोत कर जाता है। वहीं अमिश शर्मा के सम्मर्पन में खुद न्यायधीनता के लिए है सम्पूर्ण आलोचनात्मक नतीजा, बल्कि पूर्व न्यायधीनता शब्द बाबा-बाबा राजनीतिक रूप में बयान देने में है। बाह्यतः, संस्था के रूप में फैसले को लेकर शुरू हुआ विवाद अन्तर्गत न्यायपालिका की छवि और स्वतंत्रता पर विपरीत का स्पष्ट लेकूक है। अमिश शर्मा की टिप्पणी में बयान को तो तब तक, विलेन के संदर्भ में भी आलोचना के बिना को बात यह है कि पूर्व न्यायधीनता दो छोरों में टकराव न्यायधीनता की ही राजनीतिक बयान का हिस्सा बना रहे है। इस पर ध्यानमात्र से बयान प्रस्तुत उन्नीस है कि बयान न्यायधीनता को राजनीति प्रत्येक करके के बयान न्यायधीनता को आहूत लेने का सामना, या फिर उन्नीस राजनीतिक धातुपर प्रस्तुत प्रस्तुत आलोचना का चयन करना चाहिए।

सब ऐसे है! झूठ है, अवसरवाद है!

[illegible]

की मैसेजिंग के संकल्प में काम करेंगे? लाल किले से आत्मनिर्भर भारत और संघ को नमन वैसा ही छत, वैसा ही रस्मी और दिखावे की नौटंकी है, जिससे अब कुछ भी नहीं सध सकता।

[illegible]

तरुवीरों की दुनिया



जम्मू में भारी बारिश के कारण तवी नदी में उफान आने से एक



जम्मू-कश्मीर के कटरा में भारी बारिश के बाद भूस्खलन के बाद एक घायल को इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा है।



जम्मू में भारी बारिश के बाद नदी में आए उफान के कारण जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।



जम्मू के भगवती नगर में लगातार बारिश के बाद चौथे तवी पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से वाहन फंस गए।



नई दिल्ली में साक्ष्य प्रक्रिया पर एलजी की अधिसूचना के खिलाफ वकीलों ने तीस हजारी कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।



बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी।



महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई तालुका के विस्तार में एक चार मंजिला इमारत का पिछला हिस्सा एक वॉल पर गिरने के बाद बचाव अभियान चलाते एनडीआरएफ के जवान।

हू। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने अमेरिका को ४६ अरब डॉलर का अर्पण वित्त थावाल् वित्त वर्ष 2025-26 में अर्पण से जुवाङ्ग के बीच भारत ने अमेरिका में 33.53 अरब डॉलर का अर्पण किया है। उनमें यश ही कहा कि सकारा ढेरुल अर्पण के अमेरिकी दौरे के प्रभाव से वज्जने वित्त उपायों पर काम कर रही है। बावजूद मालायुय इस सप्ताह सार्याधिक, रत और अभूषण उद्ये वेङ्गे से संबन्धित हित्वाकों के साथ अर्पण के नुत बाजारों में वक्रुङ्ग के तरीकों पर चर्चा काँ वित्त वेङ्गे अर्पण कर रहा है। 2025-26 के वङ्ग में षोषित अर्पण संघर्षमि मरण के गङ्ग पर ही उँगी से काम चल रहा है, अतः, भारीय उपायों पर 50 प्रतिशत दैरिफ काम करने के कङ्ग सप्ताह के एक सप्ताहकार के दौरे। अमेरिकी अर्पणों वित्त मंत्री वेङ्गे ने भारत-अमेरिकी संबंधों को वेङ्ग उपाय नतले षोष उपाय जहाँ है कि आर्थिकार, एक षाफ काम आ जायै।

[illegible]

स्वामी कौशल किशोर मिश्र की ओर से प्रकाशक, मुद्रक सुभाष अग्रवाल द्वारा आकाश आफसेट प्रिंटर्स से मुद्रित कर तिलक मार्ग, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा से प्रकाशित, संपादक सुभाष अग्रवाल फोन: 221149, मो. : 9425224167 आर.एन.आई. पंजी. नं. 50254/89, ई-मेल tarunpresskrb@gmail.com